1	2	3	4	5
4. Gauri Fine Chemicals		8.57	3.70	n.a.
5. Reine Chemicals		0.38	—	n.a.
6. Amer Chemicals		7.59	2.96	n.a.
7. Maduker Chemicals		18.97	21.00	n.a.
8. Naform Chemicals		21.95	11.34	n.a.
II. *Phenylbutazone*	T			
1. Themis Chemicals		15.00	13.24	4.93
2. S.G. Chemicals		45.26	40.05	32.00
. Kothari Plantation		2.67	0.32	—
. Reine Chemicals		37.30	30.04	n.a.
5. Nufarm Chemicals		8.33	0 43	n.a.
6. Pharma Synth		0.34	—	n.a.
7. Swati Chemicals		11.54	11.23	n.a.

लाइटनिंग ट्रंक काल का भुगतान

618. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार पांच घंटे के बाद काल लगने पर भी लाइटनिंग ट्रंक काल की दर से ही भुगतान करना पडता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "ओडिनरी" "अर्जेंट" "इमीडिएट" और "लाइटनिंग" कालों के लगाने की अवधि और दर निश्चित है ;

(ग) क्या सरकार उपर भाग (क) में उल्लिखित उस स्थिति में जब निश्चित अवधि के अन्दर काल नहीं लगती है, ओडिनरी काल की दर से भुगतान लेने का आदेश जारी करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। लाइटनिंग काल के 15 मिनट के भीतर लग जाने की संभावना होती है। तथापि यदि काल एक घंटे के भीतर नहीं लगती है और एक्सचेंज में कार्यरत स्टाफ इसकी सूचना दे देता है, तो उपभोक्ता इस लाइटनिंग काल की श्रेणी बदल सकता है या उसे रद्द कर सकता है। यदि उपभोक्ता इसे रद्द नहीं करता या लाइटनिंग काल की श्रेणी को साधारणतया अर्जेंट काल की श्रेणी में नहीं बदलता तो काल लगने पर लाइटनिंग काल का प्रभार ही वसूल किया जाता है।

(ख) जी हां। 500 शहरों के बीच प्रभावी कालों के विलम्ब के संबध में 1990 तक विभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(i) लाइटनिंग और उच्च प्राथमिकता वाले ट्रंक काल...15 मिनट के भीतर

(ii) अर्जेंट ट्रंक काल...कुल प्रभावी कालों का 50%...30 मिनट के भीतर

कुल प्रभावी कालों का 80%...60 मिनट के भीतर

(iii) साधारण ट्रंक काल...

कुल प्रभावी कालों का 30%
30 मिनट के भीतर

कुल प्रभावी कालों का 50%
60 मिनट के भीतर

कुल प्रभावी कालों का 90%
170 मिनट के भीतर

(ग) यदि काल निर्धारित समय के भीतर नहीं लगती है तो उस मामले में लाइटनिंग काल के लिए साधारण काल का शुल्क वसूल करने संबंधी आदेश जारी करने पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसा इसलिए है कि काल बुक करने के एक घंटे बाद जब उसे एक्सचेंज द्वारा सूचित किया जाता है कि काल लगने में विलम्ब होने की संभावना है; तो उपभोक्ता को काल रद्द करने या काल की श्रेणी बदलने का अधिकार है।

Setting up of industries in backward areas

619. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a recent study has pointed out that the policy of industrial dispersal had not touched the backward areas in any tangible manner;

(b) if so, what is Government's reaction to the above observation; and

(c) what steps are being taken by Government to set up more industries in backward areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Industrialisation is a continuous process. The Central incentives provided by the Central Government have helped entrepreneurs to set up industries in backward areas as is evident from the reimbursements of central investment subsidy and number of Letters of Intent (LOIs), Industrial Licences (ILs), Delicensed Industries Registrations (DLR) and DGTD Registrations issued to industrially backward districts/areas in different States/Union Territories in the country during the last 3 years:

Reimbursements of Central Investment Subsidy

1985-86	Rs. 101.27 crores
1986-87	Rs. 125.12 crores
1987-88	Rs. 154.35 crores

No. of LOIs, ILS DLR and DGTD Registrations issued :

	LOI	IL	DLR	DGTD Regn.
1985	774	427	681	1140
1986	621	278	1483	610
1987	534	192	1097	651

मयूर बिहार की सहकारी आवास समितियों द्वारा बनाये गये फ्लैटों के लिए बिजली के कनक्शन

620. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय न होने के कारण मयूर विहार एक्सटेंशन, फेस–II में 11 किलोवाट का एक सब स्टेशन बनाये जाने का काम अब तक भी आरंभ नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मयूर विहार एक्सटेंशन में बिजली की सप्लाई न होने के कारण सहकारी आवास समितियों द्वारा बनाकर तैयार कर दिये गए सैकड़ों फ्लैटों में लोगों ने जाकर रहना शुरू नहीं किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।